



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 17 फरवरी, 2001/28 मार्च, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 17 फरवरी, 2001

संख्या एल०एल० आर०डी०(6)11/2000-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 9-2-2001 का अनुमोदित हिमाचल प्रदेश

लोक धन (देय की वसूली) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्यांक 14) को 2001 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ महित राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विधि)।

2001 का अधिनियम संख्यांक 2.

## हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 2000

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2001 को यथा अनुमोदित)

राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य निगम अथवा सरकारी कंपनी या बैंककारी कंपनी के कतिपय देयों की शीघ्र वसूली से सम्बन्धित विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 2000 है ।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(क) “बैंककारी कंपनी” से,—

- |               |  |
|---------------|--|
| 1949 का<br>10 | (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित बैंककारी कंपनी;  |
| 1955 का<br>23 | (ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;   |
| 1959 का<br>38 | (iii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक;                        |
| 1956 का<br>1  | (iv) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कृषि वित्त निगम सीमित कंपनी;                                  |
| 1981 का<br>61 | (v) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; |
| 1970 का<br>5  | (vi) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक;             |
| 1949 का<br>10 | (vii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था;  |
| 1976 का<br>21 | (viii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन गठित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक; या                          |
| 1980 का<br>40 | (ix) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है; |

(ख) “कलक्टर” से, जिला का कलक्टर अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति इस के अन्तर्गत है ;

- (ग) "निगम" से, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कोई अन्य निगम भी है ; 1951 का 63
- (घ) "वित्तीय सहायता" से, निम्नलिखित के लिए दी गई कोई वित्तीय सहायता अभिप्रेत है,—
- (i) व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए ; या
  - (ii) आवासिक भवन के निर्माण के लिए ; या
  - (iii) पेयजल, कूहल या पाइप लाईन की व्यवस्था करने के लिए ; या
  - (iv) पशुपालन, कृषि या बागवानी के विकास के लिए ; या
  - (v) किसी ग्रामीण या कुटीर उद्योग, औद्योगिक उपक्रम या कृषि उद्योग की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, नवीकरण करने या चलाने के लिए ; या
  - (vi) किसी अन्य प्रकार के योजनाबद्ध विकास के प्रयोजनों के लिए ; या
  - (vii) विपत्ति से राहत के लिए ; या
  - (viii) राष्ट्रीय उधार छात्रवृत्ति स्कीम के अधीन ऋण के लिए ; या
  - (ix) वृत्तिक/विशेषज्ञीय प्रशिक्षण, जैसा राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, जिसके सम्बन्ध में छात्रवृत्ति/वृत्तिका लोक निधि से संदत्त की जाती है और राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा दी जाती है ;
- (ङ) "सरकारी कम्पनी" से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है और जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित किया जाता है ; 1956 का 1
- (च) "औद्योगिक उपक्रम" के अन्तर्गत, माल के विनिर्माण, परिरक्षण, भण्डारकरण या प्रसंस्करण अथवा खनन या होटल उद्योग अथवा यात्रियों या माल का परिवहन या विद्युत या विद्युत शक्ति के किसी अन्य रूप में उत्पादन या वितरण अथवा मशीनों, यानों, जलयानों, नौकायान, ट्रैलरों या ट्रैक्टरों के रख-रखाव, मरम्मत, परीक्षण या मफाई-धुलाई मशीनों या बिजली की सहायता से किन्हीं वस्तुओं के समंजन, मरम्मत या पैकिंग या मछली पकड़ने या उसके रख-रखाव के लिए तट सुविधाओं की व्यवस्था करने या भूमि के किसी संलग्न क्षेत्र का औद्योगिक सम्पदा के रूप में विकास करने या औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि के लिए विशेष या तकनीकी जानकारी या अन्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई उपक्रम है ;
- स्पष्टीकरण.—"माल का प्रसंस्करण" पद के अन्तर्गत किमी सामग्री को शारीरिक, यांत्रिक, रसायनिक, विद्युत या इसी प्रकार की अन्य क्रिया के अधीन करके किसी वस्तु के उत्पादन, तैयार करने या बनाने का कोई कार्य या प्रक्रिया है ;
- (छ) "प्रायोजित स्कीम" से, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वह प्रायोजित स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन सम्बद्ध सरकार या तो,—

(i) निगम या सरकारी कम्पनी को ऋण, अग्रिम, अनुदान या सहायकी के वितरण के प्रयोजन के लिए या माल के उधार पर या अवक्रय पर विक्रय प्रयोजन के लिए अग्रिम धन देती है ; या

(ii) ऋण, अग्रिम, अनुदान या सहायकी के संदाय या उधार पर या अवक्रय पर विक्रीत माल की कीमत के संदाय की प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने के लिए सहमत होती है ; और

(च) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

3. (1) जहाँ कोई व्यक्ति या तो मूल ऋणी के रूप में या प्रतिभू के रूप में या प्रत्याभूतिदाता के रूप में निम्नलिखित में पक्षकार है--

कतिपय  
देय की  
भू-राजस्व  
की बकाया  
के रूप में  
वसूली।

(क) (i) राज्य सरकार, सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उप करार के अधीन दिए गए ऋण, अग्रिम, अनुदान, सहायकी, वित्तीय सहायता, वृत्तिका या छात्रवृत्ति से सम्बन्धी या विक्रीत माल के उधार के बारे में या अवक्रय से सम्बन्धी किसी करार या बंधपत्र का ; या

(ii) यथास्थिति, राज्य सरकार, बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन दिए गए ऋण, अग्रिम, अनुदान या सहायकी से सम्बन्धी या विक्रीत माल के उधार के बारे में या अवक्रय से सम्बन्धी किसी करार का ; या

(ख) औद्योगिक उपक्रम द्वारा दिए गए ऋण के बारे में राज्य सरकार, सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से सम्बन्धी किसी करार का ; या

(ग) किसी करार का, जो यह उपबंधित करता है कि उद्गीत सरकार को देय कोई धन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली होगी ; या

(घ) राज्य सरकार द्वारा या के माध्यम से दिए गए माल या किसी अन्य वस्तु के विक्रय या वितरण के किसी करार,

और ऐसा व्यक्ति--

(i) ऋण, अग्रिम, वृत्तिका या छात्रवृत्ति का उसके किसी किस्त या ब्याज के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम करता है ; या

(ii) अनुदान की शर्तों के अधीन, अनुदान या उसके किसी प्रभाग का प्रतिदाय करने का दायी होने पर ऐसे अनुदान या उसके प्रभाग या किस्त के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम करता है ; या

(iii) माल या किसी अन्य वस्तु की कीमत या उसके ब्याज के संदाय का दायी होने पर, उसके या उसके भाग का संदाय करने में अक्षम रहता है ; या

(iv) अन्यथा करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है ; तब, राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, और बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी की दशा में, उसका प्रबन्ध निदेशक या इस निमित्त विनिर्दिष्टतः प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो मण्डलीय प्रबन्धक की पंक्ति से नीचे का न हो । तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलक्टर को, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि को वर्णित करते हुए और यह अनुरोध करते हुए प्रमाणपत्र भेज सकेगा कि कार्यवाहियों के खर्चे सहित ऐसी कोई राशि या कोई अन्य राशि वसूल की जाए मानो यह भू-राजस्व की बकाया हो ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन भेजा प्रमाण-पत्र उसमें विवरणित विषय का निश्चायक सबूत होगा और कलक्टर ऐसे प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर उसमें विवरणित रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(3) उप-धारा (1) की कोई भी बात, किसी बन्धक, भार, गिरवी या किसी अन्य विल्लंगम द्वारा सृजित किसी सम्पत्ति में, राज्य सरकार, बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी के हित पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(4) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की सम्पत्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी के पक्ष में किसी बन्धक, भार, गिरवी या अन्य विल्लंगम के अधीन है, वहां तब—

(क) माल की गिरवी की दशा में इस प्रकार गिरवी रखे माल के विक्रय के लिए कार्यवाहियों की जाएंगी और यदि ऐसे विक्रय के आगम, देय रकम से कम है, तो ऐसे व्यक्ति की अन्य सम्पत्ति के विरुद्ध अधिशेष की वसूली के लिए कार्यवाहियों की जाएंगी :

परन्तु जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि, यथास्थिति, इसको या बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी को देय रकम की वसूली की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो यह कारणों को अभिलिखित करते हुए तब गिरवी माल से पहले या उसी समय अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाहियां करने के लिए निदेश दे सकेगी मानो कार्यवाहियां गिरवी रखे माल के विक्रय के लिए की जाती हैं ।

(ख) स्थावर सम्पत्ति पर बन्धक, भार या अन्य विल्लंगम की दशा में, यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति या, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का उसमें हित, उस व्यक्ति से देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाहियों में पहले विक्रीत किया जाएगा और अन्य कोई कार्यवाहियां केवल तभी की जा सकेंगी यदि कलक्टर प्रमाणित करे कि प्रथमतः वर्णित प्रक्रिया द्वारा युक्ति-युक्त समय के भीतर देय राशि की वसूली की कोई संभावना नहीं है ।

(5) जहां सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम के देयों के अतिरिक्त, धारा 3 में वर्णित व्यक्ति से सरकारी देय वसूली हों, वहां भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली में सरकारी देयों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

4. धारा 3 के अधीन कलक्टर की सेवाओं का उपभोग करने वाली कोई बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी ऐसी दर पर राज्य सरकार को संग्रहण प्रभार संदत्त करेगी जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। संग्रहण प्रभार।
5. (1) हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1973 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्या-वृत्तियां।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 2 of 2001.

## THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC MONEYS (RECOVERY OF DUES) ACT, 2000

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 9TH FEBRUARY, 2001)

AN

ACT

*to re-enact the law relating to the speedy recovery of certain dues of the State Government or the Himachal Pradesh Financial Corporation or any other Corporation notified by the State Government in this behalf or a Government Company or a Banking Company.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty first Year of the Republic of India, as follows:—

Short title,  
extent and  
commen-  
cement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 2000.

(2) It extends to whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Defini-  
tions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Banking Company" means,—

- (i) a Banking Company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ; 10 of 1949
- (ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955; 23 of 1955
- (iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; 38 of 1959
- (iv) the Agricultural Finance Corporation Limited, a company incorporated under the Indian Companies Act, 1956 ; 1 of 1956
- (v) the National Bank for Agricultural and Rural Development, established under the National Bank of Agricultural and Rural Development Act, 1981 ; 61 of 1981
- (vi) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 ; 5 of 1970
- (vii) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 ; 10 of 1949
- (viii) the Regional Rural Banks constituted under the Regional Rural Banks Act, 1976 ; and 21 of 1976
- (ix) a corresponding new Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 ; 40 of 1980

(b) "Collector" means a Collector of the District and includes any person appointed by the State Government to perform the functions of a Collector under this Act ;



63 of 1951

- (c) "Corporation" means the Himachal Pradesh Financial Corporation established under the State Financial Corporation Act, 1951 and includes any other Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government which the State Government may, by notification, specify ;
- (d) "financial assistance" means any financial assistance rendered,—
- (i) for the purposes of vocational or technical training ; or
  - (ii) for the construction of residential buildings ; or
  - (iii) for providing drinking water, kuhl or pipe line; or
  - (iv) for the development of animal husbandry, agriculture or horticulture; or
  - (v) for establishing, expanding, modernising, renovating or running any village or cottage industry, industrial undertaking or agro industry ; or
  - (vi) for purposes of any other kind of planned development; or
  - (vii) for relief against distress; or
  - (viii) for loans under the National Loans Scholarship Scheme ; or
  - (ix) for professional/specialised training, as may be notified, in the Official Gazette, by the State Government, in relation to which scholarship/stipend is paid out of the public funds and is imparted by the institutions of the State Government ;

1 of 1956

- (e) "Government Company" means a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 and which is notified as such by the State Government from time to time;
- (f) "industrial undertaking" includes any undertaking for the manufacture, preservation, storage or processing of goods, or mining, or the hotel industry, or the transport of passengers or goods, or the generation or distribution of electricity or any other form of power or the maintenance, repair, testing or servicing of machinery, vehicles, vessels, motor boats, trailers or tractors or assembling, repairing or packing of any articles with the aid of machinery or power or fishing or providing shore facilities for fishing or maintenance thereof, or for the development of any contiguous area of land as an industrial estate or providing special or technical knowledge or other services for promotion of industrial growth ;

*Explanation.*— The expression "processing of goods" includes any act or process for producing, preparing or making an article by subjecting any material to a manual, mechanical, chemical, electrical or any other like operation ;

- (g) "sponsored scheme" means a scheme sponsored by way of financial assistance by the State Government or the Central Government under which the concerned Government, either—
- (i) advances money to the Corporation or the Government Company for the purposes of disbursing loans, advances, grants or subsidies or for the purpose of sale of goods on credit or hire purchase ; or

(ii) guarantees or agrees to guarantee the payment of loan, advances, grant or subsidies or the payment of price of goods sold on credit or hire purchase; and

(h) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

Recovery  
of certain  
dues as  
arrears of  
land reve-  
nue.

3. (1) Where any person either as principal or as surety or as guarantor is a party—

(a) (i) to any agreement or bond, relating to a loan, advance, grant, subsidy, financial assistance, stipend or scholarship given under that agreement or relating to credit in respect of, or relating to hire purchase of goods sold by the State Government, Government Company, Banking Company, or Corporation by way of financial assistance; or

(ii) to any agreement relating to loan, advance, grant or subsidy given under that agreement or relating to credit in respect of, or relating to hire purchase of, goods sold by the State Government, a Banking Company, a Corporation or a Government Company, as the case may be, under a sponsored scheme; or

(b) to any agreement relating to a guarantee given by the State Government, Government Company, Banking Company or a Corporation in respect of a loan raised by an industrial undertaking; or

(c) to any agreement providing that any money payable thereunder to the State Government shall be recoverable as arrears of land revenue; or

(d) to any agreement to sell or distribute goods or any other article supplied by or through the State Government and such person—

(i) makes any default in the repayment of the loan, advance, stipend or scholarship or any instalment or interest thereof; or

(ii) having become liable under the conditions of the grant to refund the grant or any portion thereof, makes any default in repayment of such grant or portion or instalment thereof; or

(iii) having become liable to pay the price of the goods or any other article or interest thereof, fails to pay the same or part thereof; or

(iv) otherwise fails to comply with the terms of the agreement;

then, in case of the State Government, such officers as may be authorised in this behalf by the State Government, by notification in the Official Gazette, and in the case of Banking Company, Corporation or the Government Company, the Managing Director or any other officer not below the rank of Divisional Manager specifically authorised in this behalf, thereof, by whatever name called, may without prejudice to any other mode of recovery under any other law for the time being in force, send a certificate to the Collector, mentioning the sum due from such person and requesting that such sum together with the costs of the proceedings or any other sum be recovered as if it were an arrear of land revenue.

(2) A certificate sent under sub-section (1) shall be conclusive proof of the matter stated therein and the Collector on receiving such certificate shall proceed to recover the amount stated therein as an arrear of land revenue.

(3) Nothing in sub-section (1) shall affect any interest of the State Government, a Banking Company, a Corporation or a Government Company, in any property created by mortgage, charge, pledge or any other encumbrance.

(4) Where the property of any person referred to in sub-section (1) is subject to any mortgage, charge, pledge or other encumbrance in favour of the State Government, a Banking Company, a Corporation or a Government Company, as the case may be, then—

(a) in every case of a pledge of goods, proceedings shall first be taken for the sale of goods so pledged and if the proceeds of such sale are less than the sum due, then proceedings shall be taken for recovery of the balance against the other property of such person:

Provided that where the State Government is of the opinion that it is necessary so to do for safeguarding the recovery of the sum due to it or to a Banking Company, a Corporation or a Government Company, as the case may be, it may, for reasons to be recorded in writing, direct proceedings to be taken against the other property then the goods pledged before or at the same time as the proceedings are taken for the sale of goods pledged.

(b) in every case of a mortgage, charge or other encumbrance on immovable property, such property or, as the case may be, the interest therein of the person referred to in sub-section (1) shall first be sold in proceedings for recovery of the sum due from that person and any other proceedings may be taken only if the Collector certifies that there is no prospect of realisation of the sum due through the first mentioned process within a reasonable time.

(5) Where Government dues are recoverable from the person mentioned in section 3 in addition to dues of Government Company, Banking Company or Corporation, priority will be given to Government dues in recovery as arrears of land revenue.

4. A Banking Company, a Corporation or a Government Company availing the services of the Collector under section 3 shall pay collection charges to the State Government at such rates, as may be notified in the Official Gazette by the State Government, from time to time.

Collection charges.

5. (1) The Himachal Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1973 is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

